Fax : 0512-2332222 (S.O.)
011-23212648 (C.O.)

Ph. : 0512-2332222
Mob. : 09415726924

# सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ
# Govt. Employees National Confederation

(AFFILIATED TO B.M.S.)

CENTRAL OFFICE : RAM NARESH BHAVAN, TILAK GALI, PAHAR GANJ, NEW DELHI - 110055
SUB OFFICE : 2-A, NAVIN MARKET, KANPUR - 208 001

Ref: GENC/Cor-OFB/193(8/2/L) Date : 20.05.2020

सेवा में,

माननीय श्री राजनाथ सिंह जी,
रक्षा मंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली

विषय - आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण रोकने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निम्न तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

महोदय, मई 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे केन्द्र में राजग की सरकार का गठन हुआ। सरकार के गठन के साथ ही रक्षा क्षेत्र में एफ.डी.आई. 100% करने और आयुध निर्माणियों का निगमीकरण का प्रस्ताव तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्री महोदया के द्वारा लाने का प्रयास किया गया।

''भारतीय मजदूर संघ'' से संबद्ध ''भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ'' ने इसका कडा़ विरोध किया। तत्कालीन रक्षा एवं वित्त मंत्री स्व0 अरुण जेटली जी ने हस्तक्षेप किया तथा एफ.डी.आई. न बढाने और आयुध निर्माणियों का निगमीकरण न करने का आश्वासन दिया। महोदय कुछ ही समय बाद रक्षा मंत्री के रुप में स्व0 मनोहर पार्रिकर जी ने कार्य भार संभाला, वणिज्य मंत्रालय के द्वारा फिर से रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एफ.डी.आई. बढ़ाने और आयुध निर्माणियों का निगमीकरण करने का प्रस्ताव आया। स्व0 मनोहर पार्रिकर जी ने भी एफ.डी.आई. 49% डायरेक्ट रुट से बढाने से मना किया तथा उस समय भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से हुई वार्ता के अन्तर्गत उन्होने भी कहा था कि रक्षा क्षेत्र में एफ.डी.आई. बढ़ाने की बात सोचना गलत है। हमें अपने संसाधनों के

साथ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। साथ ही उन्होने कहा कि ओ.एफ.बी. का निगमीकरण करने से कोई लाभ नही होगा, हम इनका निगमीकरण नही करेगें। लेकिन आयुध निर्माणियो को कारपोरेट की तरह कार्य करना होगा । उन्होने यह भी कहा था कि नई तकनीकि लाने के लिए और पूँजी निवेश के लिए ज्वांइन्ट वेन्चर किये जा सकते है।

महोदय, स्व0 मनोहर पार्रिकर जी के गोवा के मुख्य मंत्री बनने के पश्चात पुनः स्व0 अरुण जेटली जी ने रक्षा मंत्रालय का भार संम्भाला उस समय आयुध निर्माणियों को पी.पी.पी. मॉडल में चलाने की चर्चा हुई । भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से वार्ता के दौरान उन्होने आश्वस्त किया था कि पी.पी.पी. मॉडल में आयुध निर्माणियो को सेफ्टी नेट प्रदान किया जायेगा और उन्होने मॉडर्नाइजेशन के अन्र्तगत आयुध निर्माणियो के किसी भी उत्पाद का 25% सेफ्टी नेट के रुप में वर्क लोड प्रदान करने की बात कही थी।

महोदय, कुछ ही दिनों बाद, वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौपा गया उनके कार्यकाल में आयुध निर्माणियों का बजट जो कि 17,000 करोंड था उसे घटाकर 6,000 करोंड़ कर दिया गया जबकि स्व0 मनोहर पार्रिकर जी ने अपने कार्यकाल में तीन वित्तीय वर्षो में आयुध निर्माणियों को क्रमशः 14,000 करोड़, 17,000 करोड़ और 20,000 करोड़ ले जाने का लक्ष्य रखा । महोदय बजट के बाद बी.एम.एस. ने वर्तमान रक्षा मंत्री महोदया से वार्ता कर पुनः बजट प्रदान करने की अपील की, अपील के बाद बजट में कुछ बढोतरी हुई। महोदय, निर्माणियों के निगमीकरण की चर्चाए 2019 में पुनः सत्तारुढ होने के बाद प्रारम्भ हुई, देश भर में कर्मचारी आन्दोलित हुए और 20 अगस्त 2019 से 25 अगस्त 2019 तक पूरे देश के रक्षा संस्थानो में हड़ताल हुई। चार दौर की वार्ता के बाद आपके हस्ताक्षेप से एक कमेटी गठित हुई जिसे यह विचार करना था कि वर्तमान स्वरुप में ही कैसे आयुध निर्माणियों को अगले तीन वर्ष मे 30,000 करोड़ तक का उत्पादन लक्ष्य पूरा कराया जा सकता है। महोदय अतिरिक्त रक्षा सचिव (डी.पी.) की चेयनमैनशिप में गठित एक कमेटी की बैठक हुई जिसमें कर्मचारी पक्ष की ओर से ''टर्म एण्ड रिफेरेन्स'' बनाने की मांग की गयी इसके बाद मीटिंग समाप्त की गई। इसके पश्चात कोई बैठक नही हुई।

महोदय, इस कोविड-19 के संक्रमण काल में अचानक आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के साथ ही रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 49% से 74% एफ.डी.आई. करने की घोषणा से कर्मचारी हतप्रभ है और कमचारियो में घोर असन्तोष व्याप्त है।

महोदय, रक्षा क्षेत्र में निगमीकरण और एफ.डी.आई. से कोई लाभ नही होगा 49% एफ.डी.आई. के कार्यकाल में देश के रक्षा क्षेत्र में कुल कितना एफ.डी.आई. आया आप स्वयं जानते है । महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने जो घोषणा की है कि आयुध निर्माणी बोर्ड को स्टाक एक्सचेन्ज में लिस्टेड किया जायेगा, इसका भी कोई लाभ होगा ऐसा प्रतीत नही होता है क्योकिं देश के निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए काम करते है और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में लाभ नही कमाया जा सकता है क्योंकि यहाँ वर्क-लोड की अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है वर्क-लोड न होने की स्थिति में कर्मचारी अपने वेतन भत्ते कहाँ से प्राप्त करेंगें। महोदय, घाटे का कारपोरेशन होने के बाद उसे निजी क्षेत्र को दिया जायेगा और निजी क्षेत्र कुछ दिन में आयुध निर्माणियों को बन्द कर देगें। रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता की बात कही जा रही है परन्तु ''भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ'' का स्पष्ट मानना है कि इस कदम से रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भारत आत्म निर्भर कभी नही हो सकता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि ओ.एफ.बी. को कारपोरेशन करने के फैसले पर पुर्नविचार किया जाए।

भवदीय

( साधू सिंह )
महासचिव